Automatic approval of foreign technology collaboration

6985. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that as a follow-up to the liberalised Industrial policy, Government have decided to accord automatic approval of foreign technology agreement in respect of certain industries;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether this apprvoal has been accorded to industries of synthetics, diamonds, welding electrodes, food processing, etc; and

(d) if not, the reasons therefor and by when a decision is likely to be taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) to (d) As spelt out in the Statement on Industrial Policy tabled in both Houses of Parliament on 24th July, 1991, the Reserve Bank of India accords automatic approval to all industries including Synthetics, Diamonds and Welding Electrodes etc; for foreign technology agreement within prescribed monetary| royalty limits i.e. those involving a lumpsum payment upto Rs. 1 crore, 5 per cent royalty for domestic sales and 8 per cent for exports, subject to a total payment of 8 per cent of sales over a 10 years period from the date of agreement or 7 years from commencement of commercial production.

Delay in clearing of projects

6986. SHRI KRISHAN KUMAR BIRLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the report appearing in the 'Business Age' dated the 18th March, 1994, regarding delays in clearing the industrial projects and payment of bribes for project clearance, despite opening up the Indian economy to greater private sector participation; and

(b) if so, what is the reaction of Government with regard thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) Yes, Sir.

(b) The Central Government is continuously inter-acting with State Governments, Financial Institutions, Industry Associations and other related agancies to ensure that Industrial Projects are implemented expeditiously.

उत्तर प्रदेश में जिला विकास केन्द्रों के प्राप्त हुए आवेदन पत्र

6987. **श्री ईश दत्त यादव :**
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में जिला विकास केन्द्रों को रोजगार शुरू करने के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) कितने आवेदन पत्रों पर ऋण की मंजूरी दी गई है और कितने आवेदन पत्रों को रद्द कर दिया गया है तथा उपरोक्त अवधि के दौरान प्रत्येक संबंधित विकास केन्द्रों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में कोई जिला विकास केन्द्र नहीं है । माननीय सदस्यों का संकेत संभवत: शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार दिलाने की योजनाओं (एस० ई० ई० यू० वाई०) और प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पी० एम० आर० वाई०) की तरफ है जिनका कार्यान्वयन जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जा रहा है । पिछले दो वर्षों के दौरान एस० ई० ई० यू० वाई० तथा पी० एम० आर० वाई० स्कीमों के अधीन प्राप्त आवेदनों तथा

बैंकों द्वारा मंजूर और नामंजूर किये गये आवेदनों का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

1. शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाने की योजना (एस० ई० ई० यू० वाई०) :

क्रमांक	वर्ष	जिला उद्योग केंद्रों में प्राप्त आवेदनों की संख्या	बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदनों की संख्या	बैंकों द्वारा अस्वीकृत आवेदनों की संख्या
1.	1992–93	39344	10013	2987
2.	1993–94	38453	8918	7332

2. प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पी० ए० एम० आर० आई०) :

1.	1992–93	योजना आरंभ ही नहीं हुई थी ।		
2.	1993–94	26851	3989	431

उद्योग विहीन जिले

6988. श्री ईशदत्त यादव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार उद्योग विहीन जिलों के संबंध में किस आधार पर निर्णय करती है और इस संबंध में मापदंड क्या हैं ;

(ख) उन्हें किस तरह से सहायता प्रदान की जाती है ; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कितने उद्योग विहीन जिलों में उद्योग खोले गये हैं और इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जिला उद्योग केन्द्र कार्य योजना, 1979–80 के अनुसार जिन जिलों में कोई बड़ा अथवा मझोला उद्योग नहीं है उन्हें "उद्योग हित जिले" के रूप में वर्गीकृत किया गया था । देश में कुल 93 जिलों को "उद्योग रहित जिले" माना गया है ।

(ख) केन्द्र सरकार उद्योग रहित जिलों में बुनियादी सुविधाओं की एक योजना चला रही थी जिसके अंतर्गत परियोजना लागत की एक तिहायी धनराशि भारत सरकार द्वारा दी जाती थी । 1988 में नयी विकास केन्द्र योजना शुरू होने से "उद्योग रहित जिलों" के लिए यह योजना समाप्त कर दी गई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

देश में तिलहनों की पिरायी क्षमता

6989. श्री राम जेठमलानी :
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्षों से देश में तिलहनों के पर्याप्त उत्पादन से तिलहन